ग्रामीण विकास और सहकारी डेरी क्षेत्र

ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन में सहकारी डेरी क्षेत्र का योगदान

प्रचलित धारणा है कि ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन सरकार का काम है और सहकारी क्षेत्र का इसमें बहुत कम योगदान है। लेकिन कुछ उदाहरणों से स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास में सहकारी क्षेत्र विशेषतः डेरी सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है।

मध्य प्रदेश में एमपी स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को सहकारी क्षेत्र से जोडते हुए डेयरी गतिविधियों का सफल संचालन किया जा रहा है एवं प्रति दिन 08 लाख लीटर से अधिक दूध संकलन किया जा रहा है।

वर्ष 2010–11 में भारत सरकार द्वारा घोषित बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज अंतर्गत डेयरी गतिविधियों को भी सम्मिलित किया गया। यह इलाका बेहद गरीबी एवं आर्थिक रूप से पिछडेपन का शिकार रहा है। मकान मिट्टी के बने हुए है। खेती जीविकोपार्जन का प्रमुख स्त्रोत है। जल आपूर्ति एवं सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं है।

पूर्व में इस इलाके में दुग्ध संस्कृति नहीं थी और घरेलू पोषण में दुग्ध उत्पादों का बहुत कम इस्तेमाल होता था। क्षेत्र के कुछ कृषकों द्वारा दूध उत्पादन पारंपरिक रूप से करते हुए अत्यंत कम मूल्य पर डब्बे वालों को (vendor) दूध विक्रय किया जाता था। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती होने के कारण उत्तर प्रदेश के कुछ निजी व्यापारियों द्वारा रू 16–17 प्रति लीटर की दर पर दूध क्रय किया जाता था जिससे उनका शोषण होता था।

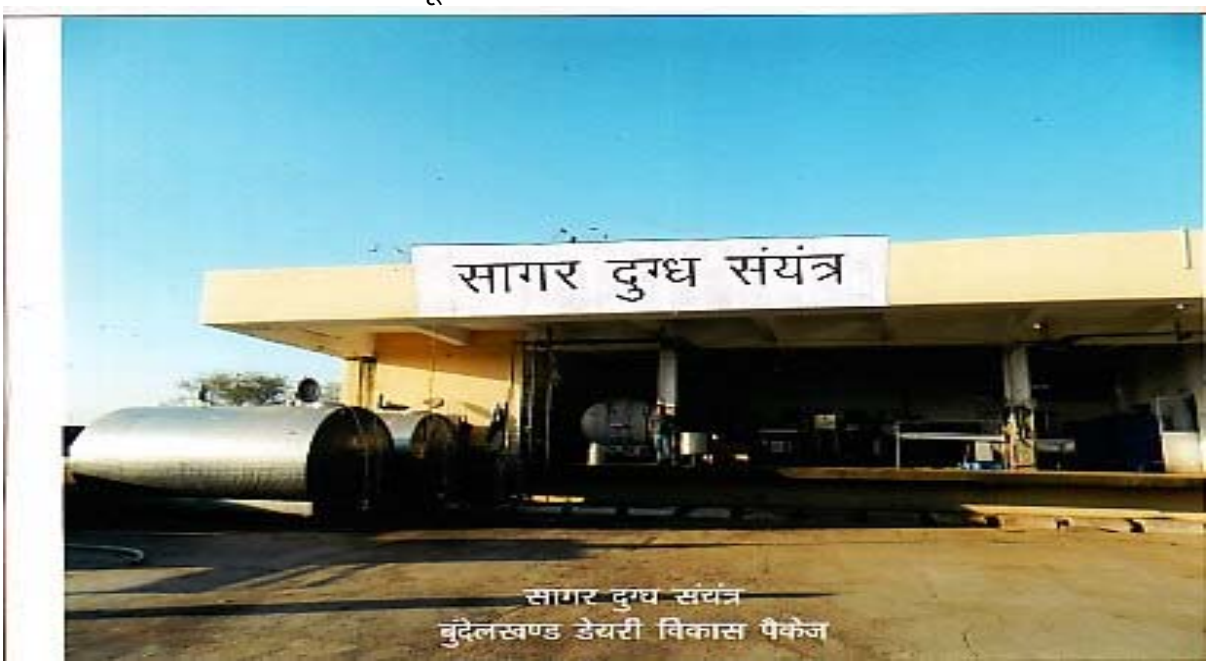

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में डेरी सहकारिता के माध्यम से परिवर्तन की बयार आई है। सहकारी दुग्ध समितियों एवं दुग्ध शीत केन्द्रों की स्थापना के प्रथम दिन 8 दिसम्बर 2010 को सागर में जिले के आठ गॉवों से लगभग 300 लीटर दूध का संग्रह किया गया। बदलाव का वाहक बनने के लिए एमपी स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा दुग्ध संघों द्वारा डेरी उद्योग के प्रति सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रवैये में परिवर्तन लाने के लिए अनेक उपाय किए गए। जिसमें असंगठित दुग्ध व्यापार को संगठित करने के लिये क्षेत्रीय दुग्ध

संघ भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर द्वारा दुग्ध मार्गों का निर्माण एवं 561 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया। ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराई, भरोसेमंद दुग्ध संग्रह तंत्र की स्थापना की गई, दूध की खरीद के लिए पारदर्शी और कड़े मानक स्थापित किए और किसानों को प्रतिस्पर्धी और लाभदायक दाम देने शुरू किये गए। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दुग्ध शीतलीकरण केन्द्रों की स्थापना की गई।

वर्ष 2012 में परियोजना का प्रथम चरण पूरा होने तक क्षेत्र में एक दिवस में अधिकतम 48,000 लीटर तक दूध का संग्रहण कर रिकार्ड कायम किये गए। मात्र एक साल में ही छतरपुर जिले की दुग्ध समिति खजवा द्वारा सहकारी क्षेत्र के मानक स्थापित करते हुए रू 34 लाख का दूध क्रय कर दुग्ध उत्पादकों को भुगतान किया गया एवं प्रथम वर्ष के शुद्ध लाभ में से लगभग 41 हजार रू का बोनस दुग्ध उत्पादकों को भुगतान किया गया।

बुन्देलखण्ड डेयरी विकास गतिविधियां होने से क्षेत्र के कुछ ग्राम संजरा, नरयावली, गणेशपुरा, खजवा आदि दुग्ध गतिविधियों के महत्वपूर्ण केन्द्र बने हुए है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की दुग्ध समिति नरयावली में दुग्ध प्रदायक दूध प्रदान करते हुए

वर्ष 2013 तक बुन्देलखण्ड क्षेत्र दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर 30 जून 2013 तक दूध उत्पादकों को रू 42 करोड़ से अधिक राशि दूध मूल्य के रूप में भुगतान की जा चुकी है। क्षेत्र में उन्नत नस्ल की दुधारू पशु न होने से कृत्रिम गर्भाधान एवं उन्नत नस्ल के सांड से नस्ल सुधार कार्यक्रम आंरभ किए गए। नियमित रूप से किसानों को मुफ्त कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा और सलाह प्रदान की। पशु स्वास्थ्य रक्षकों को कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया गया एवं 138 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना भी की गई। परियोजना अंतर्गत बीमार पशुओं के लिए पशु उपचार शिविर लगाकर पशुओं का इलाज किया गया। उच्च गुणवत्ता का पशु चारा भी उपलब्ध कराया। क्षेत्र में स्थापित कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के प्रयासों के कारण अब दूध उत्पादक उन्नत नस्लों के दुधारू पशुओं के रख–रखाव के प्रति

भी जागरूक हो रहे है एवं गायों के कृत्रिम गर्भाधान एवं उससे होने वाले दीर्घकालीन लाभ के प्रति जागरूक हो रहे है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में भी दुग्ध उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी। इसी कडी में कृत्रिम गर्भाधान कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रदेश से बाहर कोल्हापुर दुग्ध संघ एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्रों में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण करवाना प्रारंभ किया गया है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र व्यापक फैला हुआ है एवं इसमें 6000 से अधिक गॉव सम्मिलित है। वर्तमान में दुग्ध समितियां मात्र 9 प्रतिशत ग्रामों तक ही सीमित है। पूर्व में जो दूध उत्पादक अपना दूध निजी व्यापारियों को रू 16–17 प्रति लीटर बेचते थे उन्हें आज रू 27 प्रति लीटर तक का मूल्य मिल रहा है एवं अभी तक भुगतान किये गये रू 42.00 करोड बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 9 प्रतिशत ग्रामों में स्थापित दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से भुगतान किये गए।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आचार्य विद्यासागर योजना अंतर्गत पशु प्रदाय

इस इलाके के किसानों को मिलने वाली इतनी बडी राशि से उनके जीवनस्तर में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। किसानों की आमदनी बढ़ने से उनकी खर्च करने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है, अतिरिक्त सामान और सेवाओं की मांग भी बढ़ी है। सहकारी क्षेत्र में स्थापित ये दुग्ध समितियां क्षेत्र के लगभग 10,000 दुग्ध उत्पादक सदस्यों एवं 1100 कर्मचारियों को अंशकालीन रोजगार देती है। प्रत्येक परिवार के औसत 5 सदस्यों के मान से क्षेत्र में लगभग 50,000 की जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दुग्ध उत्पादन कार्य से जुडे है।

पिछले 03 वर्षों में सहकारी क्षेत्र में स्थापित इन दुग्ध समितियों के फलस्वरूप बुन्देलखण्ड क्षेत्र में डेयरी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। यह अप्रतिम उदाहरण है कि सहकारी क्षेत्र में भी किस तरह लक्ष्यों, सफलताओं, जरूरतों और विभिन्न हितों का संरक्षण होता है। दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा विकास एजेंसी का दावा किए बिना ही सजगता और विश्वास के साथ विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। क्षेत्र में आर्थिक संपन्नता लाने में ये

महत्वपूर्ण घटक साबित हुई है। इन्हीं प्रयासों के कारण बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवनस्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अनुभव बताता है कि भारत में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन में सहकारी क्षेत्र विशेषतः डेरी सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

.....